

प्रलिस फैक्ट्स: 22 अक्टूबर, 2020

- [PMKSY-AIBP के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग](#)
- [चुनावों में खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिये समिति](#)
- [उद्धान दविस](#)
- [बलु डॉट नेटवरक](#)

PMKSY-AIBP के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग

(Geo tagging of the components of projects under PMKSY-AIBP)

[प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना](#)-त्वरति सचिवाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कया गया है ।

- PMKSY-AIBP की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी वकिस और गंगा संरक्षण वभिग (Department Of Water Resources, RD & GR) के तहत की गई है ।

प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना-त्वरति सचिवाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP)

- **शुरुआत-** 1996-97 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ।
- **कार्यान्वयन-** सचिवाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिये ।
- पहले से चल रही तथा नई प्रमुख और मध्यम सचिवाई परियोजनाओं पर वचिर कया जाता है ।
- वशिष श्रेणी के राज्य/क्षेत्र की लघु सचिवाई परियोजनाओं पर भी वचिर कया जाता है ।



- [//](#) मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन का वकिस भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) की सहायता से कया है ।
- इस मोबाइल एप को वकिसति करने का उद्देश्य PMKSY-AIBP के तहत कयि जा रहे कार्यों की गततिथा परियोजनाओं की वास्तवकि स्थतिकि पता लगाना है ।
 - परियोजनाओं के अंतरगत समय-समय पर कार्यों की प्रगतिकी समीक्षा करने हेतु एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ससि्टम (MIS) भी वकिसति कया गया है ।
 - प्राथमकिता वाली परियोजनाओं के कमांड एरिया के अंतरगत फसलीकृत क्षेत्र का आकलन करने के लिये रिमोट सेंसिंग तकनीकों का भी

उपयोग किया जा रहा है।

- स्थान, नहर का प्रकार/संरचना, पूर्णता की स्थिति आदि जैसे अन्य विवरणों के साथ परियोजना घटक की छवि (Image) लेने के लिये नगिरानी टीम/परियोजना प्राधिकारी BISAG-N द्वारा वकिसति इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं।
 - प्राप्त सूचना को उपयोगकर्ता द्वारा इस उद्देश्य के लिये वकिसति GIS पोर्टल पर जियो-टैगिंग हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

जियो-टैगिंग (Geo-Tagging)

- जियोटैगिंग मेटा डेटा के रूप में भौगोलिक जानकारी को विभिन्न प्रकार से मीडिया से जोड़ने की प्रक्रिया है।
- इस मेटा डेटा में आमतौर पर अक्षांश और देशांतर जैसे निर्देशांक होते हैं, लेकिन इसमें दक्कण, ऊँचाई, दूरी और स्थान का नाम भी शामिल हो सकता है।
- जियो-टैगिंग का उपयोग आमतौर पर तस्वीरों के लिये किया जाता है और इससे लोगों को बहुत सी विशिष्ट जानकारी (जैसे- तस्वीर कहाँ ली गई थी या कसिी सर्विस में लॉग ऑन करने वाले मतिर का सटीक स्थान) प्राप्त करने में मदद मलि सकती है।

चुनावों में खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जाँच के लिये समिति

(Committee to Examine Issues Concerning Expenditure Limits)

भारतीय नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महँगाई दर में बढ़ोतरी तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

- समिति का गठन पूरव राजस्व सेवा अधिकारी और महानदिशक (अन्वेषण) श्री हरीश कुमार तथा महासचवि तथा महानदिशक (व्यय) श्री उमेश सनिहा की सदस्यता में किया गया है।
- समिति अपने गठन के 120 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौपेगी।



- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के चलते वधि और न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर, 2020 को नरिवाचन अधिनियम 1961 के नयिम संख्या 90 में संशोधन अधिसूचति कर वर्तमान खर्चों की सीमा में 10% की वृद्धि की है।
 - खर्च की सीमा में की गई यह वृद्धि वर्तमान में जारी चुनावों में भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
 - इससे पहले 28 फरवरी, 2014 को एक अधिसूचना के माध्यम से चुनावी खर्च की सीमा में वृद्धि की गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संदर्भ में 10 अक्टूबर, 2018 को इसमें संशोधन किया गया था।

यह समिति निम्नलिखित संदर्भों के आधार पर परीक्षण करेगी-

- देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव तथा खर्च पर इसके प्रभाव का आकलन।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में बदलाव और इसके चलते हाल के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले खर्च के तरीकों का आकलन।
- खर्च पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं का परीक्षण।
- अन्य संबंधित मुद्दों का भी परीक्षण।
- उपरोक्त के अलावा समिति राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से उनके विचार भी जानेगी।

खर्च में वृद्धि की आवश्यकता

- पछिले 6 वर्षों में चुनावी खर्च की सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 910 मिलियन और अब 921 मिलियन हो गई है।
- इसके अलावा लागत मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई है जो 220 से बढ़कर वर्ष 2019 में 280 और अब 301 के स्तर पर पहुँच गई है।

(Udan Day)

21 अक्टूबर, 2020 को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की चौथी वर्षगाँठ मनाई गई तथा इस अवसर पर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई क्योंकि इसी दिने 'उड़ान' योजना के दस्तावेज़ पहली बार जारी किये गए थे।



उड़ान योजना

- क्षेत्रीय संपर्क योजना- 'उड़े देश का आम नागरिक' (UDAN) भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई मार्गों द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ उपलब्ध कराना है।
- देश के उड़ान क्षेत्र में नए हवाई अड्डों और हवाई मार्ग को जोड़ने में उड़ान योजना का अहम योगदान रहा है।
- संपूर्ण भारत में उड़ान योजना के अंतर्गत 285 हवाई मार्गों के अंतर्गत 50 गैर-सेवारत अथवा सेवारत हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। इसमें 5 हेलीपोर्ट भी शामिल हैं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना के लिये बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा यह वर्ष 2024 तक 100 हवाई अड्डों/वाटरड्रोम/हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

ब्लू डॉट नेटवर्क

(Blue Dot Network- BDN)

अमेरिका में सीनेटर्स के एक द्विदलीय समूह ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक नौसैनिक अभ्यास 'मालाबार' के लिये आमंत्रित किये जाने के फैसले का समर्थन किया है और साथ ही भारत को 'ब्लू डॉट नेटवर्क' (Blue Dot Network) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है।

- ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत नवंबर, 2019 में बैंकाक (थाईलैंड) में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- यह अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम (U.S. International Development Finance Corporation) के नेतृत्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) तथा ऑस्ट्रेलिया के वदेशी मामले और व्यापार विभाग के बीच साझा सहयोग है।
- इसका उद्देश्य सरकारी, नज्दी क्षेत्रों को एक साथ लाकर साझा मानकों के दायरे में वैश्विक अवसंरचना विकास पर बल देना है।
- इसका कार्य वैश्विक अवसंरचना संधिधर्मों पर आधारित परियोजनाओं का प्रमाणन करना है।
- इस नेटवर्क द्वारा जारी प्रमाणन बाज़ार चालति, पारदर्शी तथा स्थायी विकास परियोजनाओं के लिये मान्य वैश्विक प्रतीक के रूप में कार्य करेगा।
- इस प्रकार BDN विकासशील तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था वाले देशों में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिये नज्दी पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा।
- BDN का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किये जाने के कारण इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
 - उल्लेखनीय है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि में प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने और सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था है, जबकि BDN में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।